पहले पेज से आगे

स्मार्ट सिटी योजना

रायपुर को स्मार्ट सिटी बनाने का काम शुरू हो गया है। केंद्र और राज्य सरकार से सौ-सौ करोड़ रुपये मिले हैं। इसमें से 40 करोड़ के काम शुरू करा दिए गए हैं। करीब तीन सौ करोड़ के विकास कार्यों के लिए टेंडर जारी किए जा रहे हैं। उनका कहना है कि रायपुर को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने लगातार काम हो रहे हैं। आगामी कुछ माह में यहां कई काम दिखने भी लगेंगे।

कोविंद का पर्चा

सहमति से मीरा कुमार के नाम पर मुहर लग गई। मीरा कुमार की उम्मीदवारी के बाद अब जेडीयू पर निगाहें टिकी हैं कि क्या बिहारी अस्मिता का ख्याल कर नीतीश पाला तो नहीं बदलेंगे, हालांकि जेडीयू की ओर से साफ संकेत है कि वो रामनाथ कोविंद को ही समर्थन देगी।

दो माह में शराब खपत कम, आमदनी बढ़ी

3 हजार से नीचे की आबादी के गांवों की शराब दूकानें बंद करने का फैसला लिया गया। इस वजह से 99 फीसदी गांवों में शराब दूकानें नहीं है। सरकार ने एक अप्रैल से शराब दूकानों का संचालन शुरू किया था। दो महीने में पिछले साल की तुलना में 90 करोड़ की अतिरिक्त आय हुई है। जबकि 25 फीसदी देशी-विदेशी शराब की खपत कम हुई है। जबकि शराब की कीमत में कोई खास बढ़ोत्तरी नहीं हुई है। देशी शराब की कीमत यथावत है और विदेशी शराब की कीमतों में 5 से 10 फीसदी ही बढ़ोत्तरी हुई है।

आबकारी आयुक्त अशोक अग्रवाल ने 'छत्तीसगढ़' से चर्चा में कहा कि बिना ड्यूटी के डिस्टलरी से शराब नहीं निकलने दिया जा रहा है। साथ ही रिटेल में बिक्री से भी पूरा प्राफिट सरकार को मिल रहा है। कोचियों पर पूरी तरह से अंकुश लगाया गया है। अवैध शराब बिक्री पूरी तरह से रूक गई है। उन्होंने कहा कि शराब दूकानों के संचालन में प्लेसमेंट एजेंसियों के कर्मचारियों के वेतन-दूकान किराया और बिजली बिल व परिवहन पर कुल महीने का खर्च 16 करोड़ के करीब है। उन्होंने कहा कि 30 जून तक सभी दूकानों में सीसीटीवी तक लग जाएंगे। इसके अलावा स्कैनर-प्रिंटर आदि भी उपलब्ध हो जाएगी। इसके चलते शराब बिक्री में पूरी तरह पारदर्शिता आएगी और आय भी बढ़ेगी।

जीएसटी में शुरुआत में अनजाने में हुई गलतियों

कहा कि रिटर्न दाखिल करने में अनजाने में हुई गलतियों और कर अपवंचना के लिए जानबूझकर की गई गलती में भेद किया जाएगा। अधिया ने जीएसटी टाउनहॉल में कहा, हमारी मंशा जीएसटी को सुगम तरीके से लागू करने की है। हमारा इरादा पहले महीने किसी को परेशान करने का नहीं है।

अधिया ने कहा कि हम अनजाने में हुई गलतियों के लिए काफी उदारता दिखाएंगे। यह पूछे जाने पर कि क्या शुरआती महीनों में सरकार दंड और जुर्माना प्रावधानों में उदारता दिखाएगी। उन्होंने कहा, उदारता दिखाई जाएगी, लेकिन हम इसकी घोषणा नहीं कर सकते हैं। नियमों के तहत यह व्यवस्था है कि जीएसटी परिषद निश्चित समय के लिए कुछ जरूरतों में छूट दे सकती है।

गर्भपात के लिए महिला ने दी याचिका

बोर्ड का गठन करेगा ताकि ये पता चल सके कि क्या बच्चे या मां को किसी तरह का खतरा है। कोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है और शुक्रवार को सुनवाई तय की है। गौरतलब है कि देश में कानून के मुताबिक 20 हफ्ते के भ्रूण का गर्भपात कराया जा सकता है। इसी को लेकर पहले भी सुप्रीम कोर्ट में कई मामले आ चुके हैं।

पेज 12 से आगे

बिलासपुर आबकारी के फर्जीवाड़े ...

आदेश में कहीं भी नहीं लिखा है कि चखना सेंटर चलाने की अनुमति आबकारी विभाग देगा।

इस बारे में खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग के निरीक्षक देवेन्द्र विन्ध्यराज ने बताया कि उनके पास शराब दुकानों के आसपास ठेले लगाने के लिए 40 आवेदन आए थे। इन सबको 100 रुपये की फीस लेकर अनुमति प्रदान कर दी गई है। इनको सरकारी जमीन को छोड़कर किसी भी स्थान पर चलता-फिरता ठेला चलाने की अनुमति है। शराब की बिक्री, या शराब पिलाने की अनुमति इन्हें नहीं दी गई है। जब उन्हें बताया गया कि चखना सेंटर चलाने वालों ने तो शराब पीने की सुविधा दे रखी है। उन्होंने अस्थायी ठेला लगाने की जगह टेंट लगाकर कूलर, पंखे, टेबल-कुर्सी सहित स्थायी होटल खोल रखा है। टेबल कुर्सियां भी लगा रखी हैं और खुली खाद्य सामग्री भी बेची जा रही है। उन्होंने कहा कि शराब की अवैध रूप से बिक्री या पिलाने का काम हो रहा है तो यह आबकारी विभाग को देखना चाहिए। औषधि प्रशासन विभाग सिर्फ खाद्य सामग्री की शुद्धता की जांच कर सकता है। यदि किसी ने जगह को घेरकर बिक्री शुरू की है तो नगरीय प्रशासन विभाग को कार्रवाई करनी चाहिए।

इधर नगर निगम बाजार विभाग के निरीक्षक अनिल सिंह ने बताया कि चखना सेंटर के किसी भी संचालक ने नगर निगम में ठेला लगाने की कोई अनुमति नहीं मांगी है। अस्थायी ठेलों को मामूली शुल्क के बाद यह लाइसेंस प्रदान किया जाता है। यदि नगर निगम की भूमि पर ठेला लगाया जाता है तो उससे दैनिक आधार पर शुल्क भी वसूल किया जाता है। किसी भी चखना सेंटर ने इस संबंध में कोई आवेदन नहीं दिया है। नगर निगम की भूमि पर यदि ठेला लगाया जाता है तो कार्रवाई की जाएगी।

मालूम हो कि आबकारी विभाग ने रायपुर मुख्यालय से जो परिपत्र जारी किया है, उसमें खाद्य एवं औषधि प्रशासन तथा नगरीय निकाय से अनुमति लेने की बाध्यता की गई है। लेकिन बिलासपुर में संचालित चखना सेंटर आबकारी विभाग के फर्जी आदेश पर खोल दिए गए हैं। ठेले के नाम पर लाइसेंस लेकर सर्वसुविधायुक्त 'बार' खोल दिया गया है। नगर निगम से कोई अनुमति ली ही नहीं गई है।

महासमुंद किसान खुदकुशी

बैंक, तहसील आदि से कर्ज नोटिस बकाया आदि कोई दस्तावेज नहीं है। श्री मंथीर ने अपनी कठिनाई या चिंता के संबंध में किसी को नहीं बताया है। उसके छोटे भाई जो पटवारी हैं, ने तहसीलदार को बताया है कि मंथीर ने उसे अपनी आर्थिक कठिनाइयों की कोई जानकारी नहीं दी है।

इस तरह श्री मंथीर आर्थिक तंगी या कर्ज के कारण आत्महत्या नहीं की है। इससे प्रतीत होता है कि उन्होंने किसी परिवारिक कारण आत्महत्या की हैं।

जबकि परिजनों के मुताबिक मंथीर सिंह खेती किसानी के लिए साहूकार और बैंक के कर्ज की वजह से परेशान था। मृतक किसान की पत्नी और बेटों देवीसिंह और मोहन के मुताबिक कर्ज के चलते मंथिर सिंह बहुत परेशान थे। उसने उन्नत खेती की इच्छा रखते हुए ट्रैक्टर और थ्रेसर भी खरीदा लेकिन उनकी किश्तें साल भर से बकाया है।

मृतक मंथिर की पत्नी और उनके बेटों ने बताया कि पिछले दो सालों से गांव में अकाल की स्थिति है। अच्छी फसल की पैदावार के लिए इनके पिता मंथीर सिंह नें बोर भी कराया थे लेकिन बोर फेल हो गया। इस वजह से परेशान तो रहते थे लेकिन अपने परिवार और बच्चों को परेशानी ना हो इसलिए गुमसुम रहते थे।

इधर मामले की जांच कर लौटी जिला प्रशासन की टीम ये तो मान रही है कि मृतक किसान पर कर्ज था लेकिन यह मानने से इंकार कर रही है कि उसने आत्महत्या कर्ज से किया है।

पेज 7 से आगे

जिनकी कहानियों में सेक्स अपील थी और खौफ भी

जिसके बाद अराजकता फैल गई। चीजों के दाम बढ़ गए। बेरोजगारी का आलम हो गया। सामाजिक उथल-पुथल मच गई। ब्रिटेन के यूरोप से रिश्ते बेहद खराब होने का जिक्र भी डैफ्ने ने अपने उपन्यास में किया था। जिसके बाद ब्रिटेन में इमरजेंसी लगानी पड़ी।

उपन्यास में आगे की कहानी में ब्रिटेन की मदद के लिए दोस्त अमरीका आगे आता है। फिर दोनों देश मिलकर यूएसयूके नाम का संगठन बनाते हैं। लेकिन डैफ्ने ने उपन्यास में लिखा कि इस गठबंधन के खिलाफ उसके अपने कस्बे कॉर्नवाल के लोग बगावत कर देते हैं।

दिलचस्प बात ये कि 1972 में आए इस उपन्यास के एक साल बाद ही ब्रिटेन यूरोपीय आर्थिक समुदाय का सदस्य बना था। आज जब ब्रिटेन ने यूरोपीय यूनियन से अलग होने का फैसला किया तो लगता है कि डैफ्ने ने आज का मंजर 1972 में ही बयां कर दिया था।

डैफ्ने 1908 में ब्रिटिश कस्बे कॉर्नवाल में पैदा हुई थीं। उनकी ज्यादातर जिंदगी वहीं गुजरी। उनके पिता सर जेराल्ड ड्यू मॉरिया और मां मुरिएल ब्यूमोंट भी कलाकार थे। जबकि डैफ्ने के दादा जॉर्ज ड्यू मॉरिया कार्टूनिस्ट और लेखक थे। डैफ्ने की मौत 1989 में हुई। आज भी उनके लिखे उपन्यास काफी लोकप्रिय हैं। हाल ही में बनी फिल्म माय कजिन रैशेल इस बात की मिसाल है। ये फिल्म भारत में भी रिलीज हुई थी।

ऐसा क्या हुआ कि पीएम न बन पाने के बाद अडवानी...

नेताओं को हमेशा वे आगे बढ़ाते रहे।

वे एक उदाहरण देते हुए कहते हैं, जो अडवानी नरेंद्र मोदी के लिए अटल बिहारी वाजपेयी के सामने 2002 में अड़ गए, वही अडवानी अपनी ही टीम के सबसे अहम और मजबूत नेता केएन गोविंदाचार्य के लिए वाजपेयी के सामने नहीं अड़े। मुखौटा विवाद के बाद जब गोविंदाचार्य को वाजपेयी हर हाल में सजा देना चाहते थे तो अडवानी ने उनसे एक बार भी बात करने की जरूरत नहीं समझी। वे आगे कहते हैं, दरअसल, अडवानी के कमजोर होने की शुरुआत उसी दिन से हो गई थी जब वाजपेयी ने गोविंदाचार्य को पार्टी से अलग होने के लिए बाध्य कर दिया था। अडवानी के आसपास जो उस समय के हिसाब से युवा नेता थे, उन्हें लग गया कि जब अडवानी गोविंदाचार्य जैसे नेता के लिए वाजपेयी के सामने स्टैंड नहीं ले सके तो उनके लिए तो कभी कुछ नहीं करेंगे। मोदी के मसले पर अड़कर अडवानी ने इस असर को कम करने की कोशिश की थी।

नरेंद्र मोदी की कार्यशैली को जानने वाले लोग कहते हैं कि वे न तो कभी किसी को माफ करते हैं और न ही कभी भूलते हैं। साल 2009 के लोकसभा चुनाव अभियान में जब अडवानी नेतृत्व कर रहे थे तब मोदी ने उनका पूरा साथ दिया था। लेकिन 2012 के गुजरात विधानसभा में जीत के बाद मोदी ने जब दिल्ली की ओर रुख करने की योजना पर तेजी से काम करना शुरू कर दिया तो यही अडवानी उन्हें रोकने की कोशिश करने लगे। अडवानी खुला विरोध करने के स्तर पर चले गए। जिस कार्यकारिणी में मोदी को चुनाव अभियान समिति का प्रमुख बनाने की घोषणा की उसमें अडवानी गए ही नहीं। इसके अलावा भी कई मौके ऐसे आए जब मोदी और अडवानी में स्पष्ट दूरी दिखी। कहा जाता है कि अडवानी ने एक और गलती यह की कि न तो उन्होंने मोदी का खुलकर विरोध किया और न ही पूरी तरह से भक्ति की। वे बीच का रास्ता पकड़े रहे। मोदी की कार्यशैली को जानने वाले लोग मानते हैं कि मोदी के साथ ऐसी शैली नहीं चल सकती।

कुछ राजनीतिक जानकार यह भी कह रहे हैं कि आधी सदी से अधिक का वक्त राजनीति में गुजारने वाले अडवानी यह समझ नहीं पाए कि उनके साथ दिखने वाले और उनकी टीम के तौर पर पहचान बनाने वाले अरुण जेटली, वैंकैया नायडू, अनंत कुमार और रविशंकर प्रसाद जैसे नेता उनके साथ हैं ही नहीं। जैसे ही राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में मोदी का चेहरा आगे करने की कोशिश हुई, ये सभी नेता मोदी खेमे में चले गए और नरेंद्र मोदी ने आते ही अपने विश्वस्त अमित शाह को पार्टी अध्यक्ष बनाकर यह सुनिश्चित कर दिया कि पार्टी में अब सिर्फ एक ही खेमा रहेगा और वह है नरेंद्र का खेमा। यही वजह है कि गुमनाम से रामनाथ कोविंद की उम्मीदवारी का विरोध पार्टी में कहीं से भी नहीं हो पा रहा है।

कहा जाता है कि यही अडवानी आज से 15 साल पहले यानी 2002 में उस समय के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को राष्ट्रपति बनाना चाह रहे थे लेकिन वाजपेयी ने शुरुआती स्तर पर ही इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया। अडवानी औपचारिक प्रस्ताव लेकर वाजपेयी के पास जा भी नहीं सके थे। यह भी जगजाहिर ही है कि एपीजे अब्दुल कलाम को राष्ट्रपति बनाने में भी अडवानी की ही प्रमुख भूमिका थी। लेकिन 15 साल पहले देश का राष्ट्रपति तय करने की हैसियत रखने वाले अडवानी प्रधानमंत्री के पद तक पहुंचने से चूकने के बाद अब इस पद पर पहुंचने का आखिरी मौका भी चूक गए हैं। (सत्याग्रह)

पत्रकारों को अप्रिय सत्य से बचना चाहिए-सुमित्रा महाजन

सत्य किंतु अप्रिय नहीं बोलना चाहिए। कभी कभी इसकी भी दरकार होती है।

सुमित्रा महाजन वरिष्ठ भाजपा नेता और सांसद हैं जिन्हें जून, 2014 में लोकसभा अध्यक्ष चुना गया। वे मीरा कुमार के बाद दूसरी महिला लोकसभा अध्यक्ष हैं। वे 2014 के लोकसभा चुनाव में इंदौर से आठवीं बार सांसद चुनी गईं।

क्या वसुंधरा वही गलती दोहरा रही हैं जो शिवराज ने की ?

लेकिन किसानों का कर्ज माफ करने और लागत के आधार पर उपज का समर्थन मूल्य तय करने जैसी बड़ी मांगें पूरी हुए बिना उन्होंने आंदोलन समाप्त क्यों कर दिया ? इस सवाल पर गंदालिया कहते हैं, ये दोनों मांगें अहम हैं। हम इन पर कायम हैं। सरकार ने हमसे वादा किया है कि विधानसभा के आगामी मानसून सत्र में एक दिन सिर्फ किसानों पर चर्चा की जाएगी। लोकतंत्र में समाधान ऐसे ही निकलते हैं। यदि सरकार समझौते पर अमल नहीं करेगी या किसानों के हितों की अनदेखी करेगी तो हम फिर से आंदोलन करेंगे। उनकी दलील है कि राज्य सरकार के पांच मंत्रियों और भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष ने जिस तरह से उनके साथ 11 घंटे चर्चा की, उससे साफ है कि सरकार किसानों के प्रति गंभीर है।

हालांकि प्रदेश के बाकी किसान संगठन भारतीय किसान संघ के तर्कों से इत्तेफाक नहीं रखते। राष्ट्रीय किसान महापंचायत के अध्यक्ष रामपाल जाट पूरे घटनाक्रम को सरकार और भारतीय किसान संघ के बीच नूरा कुश्ती करार देते हैं। वे कहते हैं, राजस्थान में भारतीय किसान संघ का आंदोलन हमारे बाद शुरू हुआ और इसमें हमसे कम किसान शामिल हुए। फिर भी सरकार ने केवल उन्हें ही वार्ता के लिए बुलाया। दोनों के बीच जो समझौता हुआ है उससे ही स्पष्ट हो जाता है कि आंदोलन और समझौते की स्क्रिप्ट पहले ही लिखी जा चुकी थी। भारतीय किसान संघ ने आंदोलन समाप्त किया होगा, लेकिन हमारा आंदोलन मांगें पूरी नहीं होने तक जारी रहेगा। आने वाले दिनों में हम इसे और तेज करेंगे।

अखिल भारतीय किसान सभा के अमराराम को भी यह शिकायत है कि लंबे समय से आंदोलनरत होने के बाद भी हमें सरकार ने वार्ता के लिए नहीं बुलाया। वे कहते हैं, जिनके साथ किसान हैं उन्हें तो सरकार ने बातचीत के लायक भी नहीं समझा। सरकार और भारतीय किसान संघ के बीच जो समझौता हुआ है वह आंदोलन को भ्रमित करने की साजिश है। प्रदेश की किसान विरोधी सरकार की नीतियों पर पर्दा डालने के लिए आरएएस का किसान संगठन इस तरह के हथकंडे अपना रहा है। चाहे कितनी भी कोशिश हो, किसान भ्रमित नहीं होंगे। मांगें पूरी नहीं होने तक आंदोलन जारी रहेगा। हम इसकी धार और तेज करेंगे।

राष्ट्रीय किसान महापंचायत और अखिल भारतीय किसान सभा की प्रतिक्रिया को देखकर यह कहना गलत नहीं होगा कि आने वाले दिनों में राजस्थान में किसान आंदोलन तीव्र हो सकता है। हालांकि सूबे के गृहमंत्री गुलाब चंद कटारिया इससे सहमत नहीं हैं। वे कहते हैं, किसानों और सरकार के बीच समझौता हो गया है। सरकार किसानों की समस्याओं के समाधान के प्रति गंभीर है। यदि उपद्रवी तत्व किसानों के नाम कानून को अपने हाथ में लेंगे तो सरकार उनसे पूरी सख्ती से निपटेगी। हमारा प्रशासनिक तंत्र पूरी तरह से सक्रिय है। (सत्याग्रह)

पेज 9 से आगे

एसिड पीड़िता चंचल की हुई मौत

घटना के 12 दिनों के बाद चारों की गिरफ्तारी हुई थी। इस मामले में चारों आरोपित जेल भी गये थे, लेकिन एक साल पूर्व वे सभी जमानत पर छूट गये थे

चंचल का बिना पोस्टमार्टम कराये ही दाह-संस्कार छितनावां घाट पर कर दिया गया। सूत्रों के अनुसार चंचल के चाचा नरेश पासवान ने इसकी पुष्टि की है। दाह-संस्कार के बाद सवाल उठ रहे हैं कि अब पुलिस इस बात की जांच कैसे करेगी कि उक्त एसिड पीड़िता की मौत का क्या कारण था ?

अगर एसिड के प्रभाव के कारण उसकी मौत हुई, तो फिर हत्या के प्रयास के बजाय उक्त केस हत्या में परिणत हो जायेगा। अगर अन्य कारण होंगे, तो फिर उन्हीं आईपीसी की धाराओं में केस चलेगा। शव का पोस्टमार्टम होने पर पुलिस को इस बिंदु पर जांच करने में मदद मिल सकती थी, लेकिन बिना पोस्टमार्टम के ही दाह-संस्कार होने से केस के जांच की दिशा क्या होगी, बताना मुश्किल है।

काउंसिलिंग 27 को

महासमुन्द, 23 जून। प्रयास आवासीय विद्यालयों में वर्ष 2017-18 में प्रवेश लिए से 7 जून को प्रयास आवासीय विद्यालय गुढ़ियारी, रायपुर में काउन्सिलिंग आयोजित की गई थी। काउन्सिलिंग उपरांत रिक्त सीटों पर द्वितीय काउन्सिलिंग 27 जून 2017 को सवेरे 11 बजे से प्रयास आवासीय विद्यालय गुढ़ियारी रायपुर में रखी गई है।

आदिवासी विकास विभाग के सहायक आयुक्त ने बताया कि इस काउन्सिलिंग में पूर्व को हुए काउन्सिलिंग में अनुपस्थित रहें विद्यार्थियों को पहले एवं इसके बाद प्रतीक्षा सूची वाले विद्यार्थियों को अवसर प्रदान किया जाएगा। प्रयास आवासीय विद्यालय में चयनित विद्यार्थियों के पालकों/अभ्यर्थियों को आग्रह किया गया है कि वे अपने साथ दो पासपोर्ट फोटो कक्षा दसवीं बोर्ड परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने की अंक सूची, छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी प्रमाण पत्र तथा अनुविभागीय अधिकारी राजस्व द्वारा जारी स्थाई जाति प्रमाण पत्र लाना अनिवार्य है।

टीडीएस करदाताओं को जीएसटी प्रणाली की जानकारी देने के लिए सेमीनार

छत्तीसगढ़ संवाददाता

महासमुन्द, 23 जून। एक जुलाई 2017 से छत्तीसगढ़ सहित पूरे देश के साथ वस्तु व सेवा कर लागू होना प्रस्तावित है। इसके तहत पुराने वैट पंजीकृत करदाताओं के साथ टी.डी.एस. करदाताओं का नामांकन एवं माइग्रेशन की प्रक्रिया चल रही है। इस संबंध में टी.डी.एस. करदाताओं को जीएसटी प्रणाली के जानकारी देने के लिए सेमिनार (कार्यशाला) आज 23 जून को वाणिज्यिक कर अधिकारी कार्यालय में आयोजित किया गया। जिला वाणिज्यिक कर अधिकारी ने बताया कि कार्यषाला में व्यवसायियों/करदाताओं को वाणिज्यिक कर विभाग से उपलब्ध कराये गये प्रोविजनल आईडी एवं पासवर्ड से नामांकन कर माईग्रेशन किया जाना है।

उन्होंने बताया कि पंजीयन से संबंधित जानकारियाँ जैसे कि व्यवसाय/करदाता का नाम, प्रोपराईटर/पार्टनर/कर्ता नाम, व्यवसाय स्थल, वस्तु से संबंधित कोड, बैंक खाता, फोटो, आधार कार्ड, पार्टनरशीप डीड एवं कंपनी से जुड़े अन्य दस्तावेज भी अपलोड किया जाना है। इसके साथ ही ई सींग डीएससी द्वारा वेरिफिक्केशन कर एआरएन जनरेशन का कार्य अभी किया जाना है। एआरएन जनरेशन के बिना वैट से जीएसटी में माइग्रेशन अपूर्ण है। सभी शासकीय विभाग तथा अन्य उपक्रमों को जिनके द्वारा क्रय किए जाने वाले माल एवं संकर्म संविदा के संबंध में टीडीएस की कटौती की जाती है, जीएसटी प्रणाली में अनिवार्य रूप से पंजीयन प्राप्त करना आवश्यक है साथ ही टीडीएस की राशि ऑनलाईन/मैनुअल जीएसटी पोर्टल के माध्यम से जमा कराए जाने के साथ-साथ प्रत्येक माह ऑनलाईन विवरणी प्रस्तुत कराना अनिवार्य है।

उन्होंने यह भी बताया कि टीडीएस की राशि एवं विवरणी निर्धारित समयावधि में जमा नहीं किए जाने की स्थिति में जीएसटी अधिनियम के अंतर्गत शास्ति के प्रावधान है। शासकीय विभागों के आहरण एवं संवितरण अधिकारियों को उक्त प्रावधानों एवं नियमों की संपूर्ण जानकारी होना अत्यंत आवश्यक है। कार्यशाला में जानकारी देने के लिए महेन्द्र धनेलिया, सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर, रायपुर द्वारा टी.डी.एस. करदाताओं (शासकीय विभाग) को पंजीयन हेतु नामांकन एवं माइग्रेसन की प्रक्रिया एवं अन्य संबंधी जानकारी देने के लिए उपस्थित थे।

चिकित्सालयों में सभी सुविधाएं उपलब्ध हो-कलेक्टर

राजनादगाव, 23 जून। कलक्टर भीम सिंह ने कहा कि जिले के शासकीय चिकित्सालयों में सभी प्रकार की सुविधाएं अनिवार्य रूप से उपलब्ध होनी चाहिए। कलेक्टर श्री सिंह 22 जून को कलेक्टोरेट सभाकक्ष में आयोजित स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक में विभागीय अधिकारियों को उक्ताशय के निर्देश दे रहे थे। उन्होंने जिले के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को मॉडल बनाने के निर्देश अधिकारियों को दिए। बैठक में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. मिथलेश चौधरी, जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. एलएस आंचला एवं जिला टीकाकरण अधिकारी डॉ. बीएल कुमरे एवं अधिकारीगण उपस्थित थे।

बैठक में कलेक्टर ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को सख्त चेतावनी देते कहा कि स्वास्थ्य संबंधी कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कलेक्टर ने कहा कि जिले के सभी शासकीय चिकित्सालयों में दवाईयां, उपकरण साहत सभा सामग्रा उपलब्ध हान क साथ-साथ अधोसंरचना से संबंधित कार्य भी पूरा होना चाहिए। इसके साथ ही चिकित्सालयों में चिकित्सकों एवं अधिकारी-कर्मचारियों की 24 घंटा उपस्थिति सुनिश्चित कराने तथा साफ-सफाई की भी पुख्ता प्रबंध कराने के निर्देश दिए।

कलेक्टर ने जिले के दुरस्थ एवं वनांचल क्षेत्र के चिकित्सालयों में बेहतर से बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने को कहा।

कलेक्टर ने चिकित्सा अधिकारियों को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में भर्ती मरीजों को नि:शुल्क भोजन एवं वाहन आदि की सुविधाएं भी अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए। जिले में संस्थागत प्रसव के अंतर्गत हासिल किए गए उपलब्धियों की समीक्षा करते कहा कि जिले में किसी भी स्थिति में शत-प्रतिशत संस्थागत प्रसव के लक्ष्य हासिल होनी चाहिए।

उन्होंने टीकाकरण के कार्य को भी अत्यंत महत्वपूर्ण बताते हुए इस कार्य का प्राथामकता क साथ पूरा करन क निर्देश दिए। उन्होंने मितानिनों को प्रदान की जाने वाली प्रोत्साहन राशि की उपलब्धता के संबंध में जानकारी ली। उन्होंने जिले में चिकित्सकों, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं सहित स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी-कर्मचारियों के रिक्त पदा क सबध म भा जानकारा ला। रिक्त पदों की पूर्ति हेतु शासन को पत्र लिखने के निर्देश दिए। बैठक में जिले के सभी खंड चिकित्सा अधिकारी, चिकित्सा अधिकारी सहित स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी कर्मचारीगण उपस्थित थे।

ज्ञानदीप शाला में योगाभ्यास

नवापारा-राजिम, 23 जून। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर ज्ञानदीप शिशु मंदिर उच्चतर माध्यमिक शाला में योगाभ्यास किया गया। जिसमें कपालभारती, वृक्षासन, ताड़ासन, अर्ध्दचक्रासन, वज्रासन के आसान तरीके छात्र-छात्राओं को बताये गये। जिससे छात्र-छात्राओं को एक नई अनुभूति की प्राप्ति हुई। इस अवसर पर सभी छात्र-छात्राओं ने शपथ ली कि हम प्रतिदिन योग करेंगे और निरोग रहेंगे।

इसी के साथ जनजागरण रैली का आयोजन किया गया, जिसमें छात्र-छात्राओं व्दारा नारा लगाया गया कि करें योग रहें निरोग। उक्त कार्य के लिए नगर के गणमान्य नागरिकों ने संस्था के प्राचार्य के इस कार्य के लिए प्रशंसा की। रैली के समापन पर विद्यालय की प्राचार्य रेखा तिवारी द्वारा योग के महत्व को बताते हुए कहा कि योग एक ऐसी विधि है जिसमें शरीर के सारे बीमारियों का इलाज हो जाता है। ये योग अभी का नहीं बल्कि प्राचीन कला है। विद्यालय के प्रधानाचार्य अशोक तिवारी ने बताया कि योग का अर्थ आत्मा और परमात्मा का मिलन है। योग के महत्व पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने आगे कहा कि कुछ देर का योग लेकिन लम्बे समय तक शरीर का साथ देता है।

गाय के संरक्षण-संवर्धन पर चर्चा

छत्तीसगढ़ संवाददाता

गरियाबंद, 23 जून। राष्ट्रीय स्वंयसंघ राजिम विभाग गौ सेवा प्रमुख डॉ. चन्द्रशेखर हरित के संयोजकत्व व नेतृत्व में किसान गौशाला भिलाई में गौ सेवा, पालन पोषण, संरक्षण व संवर्धन को सर्वव्यापी व सर्व उपयोगी बनाने के उद्देश्य से चिंतन मनन किया गया। जिले के सभी गौशालाओं के अध्यक्ष, प्रतिनिधियों व गौ भक्तों की उपस्थिति में उक्त कार्य को सतत गतिमान के लिए सर्व सम्मति से वृहत जिला टोली का गठन किया गया।

गौ संवा पालन पोषण संरक्षण व संवर्धन के लिए आयोजित बैठक के मुख्य अतिथि राष्ट्रीय स्वंयसेवक संध के विभाग प्रचारक श्री महावीर ने कहा कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ देश में सेवा के क्षेत्र में अनेक कार्य कर रहा है। जिसमें गौ सेवा का क्षेत्र भी एक प्रमुख एवं महत्वपूर्ण है। उन्होंने जिला टोली के सदस्यों को कहा कि अपने अपने कार्य भूमिका का जवाबदारी एवं ईमानदारी के साथ निभाते हुए आगे लाने में पुण्य सेवा देवें।

इस अवसर पर विभाग प्रमुख डॉ. हरित ने गौ सेवा विभाग की योजना एवं कार्य पर विस्तारपूर्वक प्रकाश डालते हुए कहा कि यह कार्य समाज के लिए परम उपयोगी है। बैठक समापन होने पर गौशाला के संचालक कृष्णा प्रसाद सिन्हा ने धन्यवाद एवं साधुवाद दिया एवं अगली बैठक 26 एवं 27 जुलाई को कोसरंगी महासमुन्द गौशाला एवं गुरूकुल आश्रम में रखना तय किया गया।

सेंटर आफ एक्सलेंस बनेंगे जिले के कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय

महासमुन्द, 23 जून। जिले में संचालित कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालयों को सेंटर आफ एक्सलेंस बनाया जाना है। जिसके तहत के.जी.बी.व्ही में विषयवार रिक्त पदों को योग्य एवं मेहनती महिला स्टॉफसे भरा जाना है। आरटीई नार्म्स के अनुसार के.जी.बी.व्ही में एक अधीक्षिका एवं 4 शिक्षक पंचायत (महिला) का पद स्वीकृत है। के.जी.बी.व्ही बंसुला (बसना) में गणित एवं भाषा के रिक्त पद तथा के.जी.बी.व्ही सुनसुनिया (बागबाहरा) में गणित की शिक्षिका (शिक्षक पंचायत) की आवश्यकता है। इसके लिए इच्छुक महिला शिक्षक पंचायत से 10 जुलाई तक आदेवन मंगाए गए है। इच्छुक महिला शिक्षक पंचायत सादे कागज में सम्पूर्ण बायोडाटा सहित आवेदन कार्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी बसना एवं कार्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी बागबाहरा में जमा कर सकते हैं।

सामुदायिक भवन व मटन मार्केट में निर्माण कार्य का भूमिपूजन

छत्तीसगढ़ संवाददाता

राजनांदगांव, 23 जून। महापौर मधुसूदन यादव के करकमलों द्वारा वार्ड नं. 36 रामदेव बाबा मंदिर में विधायक निधि अंतर्गत लगभग 5.60 लाख रुपए की लागत से सामुदायिक भवन निर्माण एवं वार्ड नं. 39 नंदई मटन मार्केट में अधोसंरचना मद अंतर्गत लगभग 47.00 लाख रुपए की लागत से सार्वजनिक भवन निर्माण कार्य का भूमिपूजन अलग-अलग आयोजित कार्यक्रम में किया गया। वार्ड नं. 36 व 39 के कार्यक्रम में निगम अध्यक्ष शिव वर्मा, देवशरण सेन, मनोज लोढ़ा, शरद सिन्हा, रमेश नारायणी उपस्थित थे। इस दौरान दोनों वार्ड के लोगों ने अतिथियों का स्वागत किया।

कार्यक्रम में महापौर श्री यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह द्वारा शहर विकास के लिए समय-समय पर राशि प्रदान की जाती है और अधोसंरचना मद अंतर्गत प्रदत्त 30 करोड़ रुपए में से वर्तमान में शहर में विकास कार्य कराए जा रहे हैं। इसी कडी में आज रामदेव बाबा मंदिर में सामुदायिक भवन निर्माण व नंदई मटन मार्केट

में सीमेंट कांक्रीटिंग रोड निर्माण कार्य का भूमिपूजन किया जा रहा है। भवन में और कार्य कराए जाने के लिए महापौर निधि से 2 लाख रुपए दिए जाने की घोषणा करता हूं। उक्त निर्माण कार्य गुणवत्ता के साथ अतिशीघ्र पूर्ण कराया जाएगा। मदन मार्केट में व्यवसायियों की सुविधा के लिए 2 बोर खनन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री व सांसद की मंशानुरूप वार्डों में इसी प्रकार के विकास कार्य कराए जाएंगे। इस अवसर पर वार्डवासी उपस्थित थे।